रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2006/माघ 27, 1927
No. 146] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2006/MAGHA 27, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2006

सं. 46(आर ई-2005)/2004—2009

का.आ. 218(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विदेश व्यापार नीति 2004—2009 में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.1.13 के अंत में निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी :—

"इसके अलावा, अग्रिम लाइसेंसधारक द्वारा आयात करने के लिए राज्य व्यापार उद्यम, यदि वे चाहें तो, "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी करने हेतु अनुमत हैं, तथापि, लाइसेंसधारक को संबंधित राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) को ऐसे "अनापत्ति प्रमाणपत्र" के मद्दे किए गए आयातों के तिमाही विवरण प्रस्तुत करने होंगे और इसके उपरांत एसटीई (राज्य व्यापार उद्यम) ऐसे आयातों के अर्धवार्षिक आयात आंकड़े निगरानी हेतु संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करेगा जिसकी एक प्रति वाणिज्य विभाग को पृष्ठांकित की जाएगी।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/अधिसूचना/ ए एम 06/पी सी-I]

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2006

No. 46(RE-2005)/2004—2009

S.O. 218(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy, 2004—2009 :—

1. At the end of Para 4.1.13 of the Foreign Trade Policy, the following clause should be added :—

"In addition, the State Trading Enterprises are permitted to issue 'No Objection Certificate', if they so desire, for import by advance licence holder. However, the licensee would be required to file Quarterly Returns of the imports effected against such 'No Objection Certificate' to the concerned State Trading Enterprises (STEs) and the STEs, in turn, would submit half-yearly import figures of such imports to the concerned Administrative Department for monitoring with a copy endorsed to the Department of Commerce."

This issues in public interest.

[F. No. 01/94/180/Notification/AM 06/PC-I]

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade & ex-officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.